रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) भारतीय रेल वित्त निगम ने बैंकों में कोई राशि जमा नहीं कराई थी। इसलिए बैंकों द्वारा पुनर्भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बैंक का नाम	बैंक द्वारा रोके गए मार्च 1994 के इश्यू के 10.5% कर मुक्त बांडों की संख्या		रकम (रुपयों में)
1.	भारतीय स्टेट बैंक	20,00,000	200 करोड़
2.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,50,000	35 करोड़
3.	विजय बैंक	3,50,000	35 करोड़
4.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1,00,000	10 करोड़
5.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	50,000	5 करोड़

Hostel Facility in Kendriya Vidyalayas

2020. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas opened so far in the North-Eastern States;

(b) whether the Kendriya Vidyalayas have not provided hostel facilities to the students; and

(c) if so, the reasons therefor and when will this facility be extended?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) At present there are 82 Kendriya Vidyalayas and 46 Navodaya Vidyalayas in North Eastern States.

(b) and (c) There is no hostel facility attached to any Kendriya Vidyalaya in the North Eastern States as Kendriya Vidyalayas are non-residential schools in character. However, limited hostel fcilities are available for the children of the residence of some border/hilly areas in Vishesh Kendriya Vidyalaya, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

किसानों के लिये वैज्ञानिक ढंग से भंडारण करने की सुविधाएं

2021. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, विशेष रूप से सीमान्त किसानों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले किसानों को वैज्ञानिक ढंग से अनाज भंडारण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत वर्ष के अंत तक राज्यवार ऐसे कितने गोदाम स्थापित किये गये हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को वैज्ञानिक ढंग से अनाज भंडारण की सुविधाएं प्रदान करने की कोई नई स्कीम शुरू करने की कोई योजना नहीं है। फिर भी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिए ऐसी कृषि सहकारी समितियों को जिनके सदस्य कमोवेश छोटे और सीमान्त किसान हैं, वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ये सहायता तीन

अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं जैसे बिहार में ग्रामीण विकास केन्द्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित/न्यूनतम विकसित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सहकारी विपणन, परिसंस्करण और भंडारण कार्यक्रमों के लिए सहायता संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास की अपनी योजना

31.3.1996 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की वित्तीय सहायता सहकारिता के क्षेत्र में कुल 135.49 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले 54898 ग्रामीण गोदामों तथा 9363 विपणन गोदामों का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता प्राप्त गोदामों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31.3.1996 तक निर्मित गोदामों की राज्य-वार संख्या

(क्षमता टनों में)

क्र०सं०	राज्य	निर्मित गोदाम		
		ग्रामीण	विपणन	क्षमता (ग्रामीण व विपणन)
	(क) न्यूनतम विकसित राज्य			
1.	अरूणाचल प्रदेश	0	5	2500
2.	असम	762	263	292740
3.	मणिपुर	162	19	26280
4.	मेघालय	72	58	33350
5.	मिजोरम	71	5	8115
6.	नागालैंड	79	14	13000
7.	सिक्किम	0	0	0
8.	त्रिपुरा	183	20	24835
	उप-योग (क)	1329	384	400820
	(ख) अल्पविकसित राज्य			
3.	बिहार	2410	496	553100
2.	हिमाचल प्रदेश	1634	203	202050
3.	जम्मू और कश्मीर	133	45	23200
4.	उड़ीसा	1948	588	479630
5.	राजस्थान	4308	378	496120
6.	पश्चिम बंगाल	2494	469	448260
	उप-योग (ख)	12927	2179	2202360
	(ग) विकसित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश			
1.	आन्ध्र प्रदेश	4003	571	690470
2.	गुजरात	1815	401	372100
3.	हरियाणा	1454	376	693960
4.	कर्नाटक	4510	903	879070
5.	केरल	1862	124	297030
6.	मध्य प्रदेश	5227	915	1181250
7.	महाराष्ट्र	3851	1477	1902320
8.	पंजाब	3884	831	1987190
9.	तमिलनाडु	4757	409	956578

10.	उत्तर प्रदेश	9279	787	1967750
11.	संघ शासित प्रदेश	0	2	8550
12.	राष्ट्रीय स्तर के संघ	0.42	4	9400
	उप-योग (ग)	40642	6800	10945668
	कुल योग: (क)+(ख)+(ग)	54898	9363	13548848

Environment Fund

2022. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FOREST be pleased to state:

(a) whether the Environment Fund designed to be utilised in the eventuality of a Bhopal like tragedy is stagnating in the absence of guidelines on its management from Government;

(b) if so, the difficulties that lie in the way of Government to issue the guidelines; and

(c) the steps being taken to issue them and thus enabled the Insurance Companies to invest the corpus of the Fund?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) to (c) Presently, the General Insurance Corporation and its subsidiaries are maintaining the Environment Relief Fund in short term deposits in accordance with the instructions provided by this Ministry. Detailed guidelines are under finalisation and shall be published in the scheme for establishing and maintaining the Environment Relief Fund. The modalities to reinvest the fund have also been incorporated in the scheme.

Short-Term Loans to State Governments During Kharif and Rabi Seasons

2023. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government had recently been providing short-term loans to State Governments for kharif and Rabi seasons but the same has since been discontinued;

(b) whether Government propose to revive the same; if not, the reasons therefor; and

(c) the number of projects to whom assistance was made available during the last three years, year-wise?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) Central Government was providing short-term loans to State Governments for Kharif and Rabi seasosn separately every year till Kharif 1993 to help them purchase agricultural inputs, namely, fertilizers, seeds and pesticides and make them available to farmers in time. Short-term loans to the State Governments have been discontinued from Rabi 1993-94 as no budget provision has been made for the purpose. There is no proposal, at present, to review the scheme.